सन २०१६-१७ करिता आदिम जमाती संरक्षण योजनेंतर्गत Integrated Agriculture development Plan for PVTG Beneficiaries from FRA याकरिता प्राप्त रु.८००.०० लक्ष निधीमधुन ५१ वनपट्टे धारक आदिम जमाती शेतक-यांना ९५ टक्के अनुदानावर ०.२० हेक्टर क्षेत्रावर शेडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे" या कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२१/प्र.क्र. १९३/का-१९ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ तारीख: ३१/०३/२०२२

संदर्भ-

- १. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.११०१५/४(१४)/२०१६-Grants दि.१/३/२०१७
- २. शासन निर्णय क्रमांक: आदिम २०१७/प्र.क्र. ०४/का-१९, दि. २१/०३/२०१७
- ३. आयुक्त, आदिवासी विकास यांचे पत्र क्र. आदिम २०२१/प्र.क्र.०३/का.८(६)/६५७०, दि. ०३/१२/२०२१

प्रस्तावना -

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) व आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजना अंतर्गत राज्य शासनास अनुदान प्रदान होत असते. या योजनाअंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये प्राप्त होणा-या अनुदानासाठी केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आले. सदर प्रस्तावांमध्ये "Integrated Agriculture development Plan for PVTG Beneficiaries from FRA " या प्रकल्पाचा समावेश होता. वनपट्टे धारक आदिम जमातीच्या शेतक-यांना प्राप्त जमीनींच्या एकात्मिक विकासाद्वारे त्यांच्या कुटूंबांचा आर्थिकस्तर उंचावून त्यांचे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी करणे व त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा उद्देश सदर प्रकल्पाचा आहे.

- २. जनजाती कार्य मंत्रालयाने सन २०१६-१७ करिता दि. ०८/०२/२०१७ रोजी आयोजित केलेल्या Project Appraisal Committee (PAC) बैठकीमध्ये " सन २०१६-१७ करिता आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत " Integrated Agriculture development Plan for PVTG Beneficiaries from FRA " हा रु. ८००.०० लक्ष चा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. वनहक्क कायद्याद्वारे जिमनी प्राप्त असणाऱ्या आदिम जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या जिमनीत संरक्षित शेती पध्दतीचा अवलंब करुन उच्च दर्जाचे व निर्यातक्षम उत्पादनाद्वारे शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावणे या उद्देशाने राज्यातील ५१ वनपट्टे धारक आदिम शेतक-यांना प्रती शेतकरी ०.२० हेक्टर क्षेत्रावर शेडनेट उभारणी करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त आदिवासी विकास यांनी संदर्भ ३ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे.
- 3. सदर प्रस्तावानुसार राज्यातील आदिम जमातीमधील ५१ वनपट्टे धारक शेतक-यांना प्रति शेतकरी ०.२० हेक्टर क्षेत्रावर शेड नेट उभारणी करण्याकरीता अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. याकरिता प्रति लाभार्थी रु. १६,३२,०००/- इतका खर्च प्रस्तावित आहे. याकरिता ९५% शासन अनुदान देणेत येईल तर ५% हिस्सा लाभार्थ्यांने देणे अपेक्षित आहे. यानुसार प्रति लाभार्थी रु. १५,५०,४००/- शासन अनुदान तर रु.८१,६००/- इतका हिस्सा लाभार्थ्यांणे देणे प्रस्तावित केले आहे. याप्रमाणे एकुण ५१ लाभार्थ्यांकरीता रु. ७,९०,७०, ४००/- शासन अनुदान व रु. ४१,६१,६००/- इतका लाभार्थी हिस्सा असा एकुण

रु. ८,३२,३२,०००/- इतक्या निधीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय-

वनहक्क कायद्याद्वारे जिमनी प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जिमनीत संरक्षित शेती पध्दतीचा अवलंब करुन उच्च दर्जाचे व निर्यातक्षम कृषि उत्पादन घेवून उत्पन्नात वाढ करून त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावणे या दृष्टिकोनातून विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन २०१६-१७ करीता मंजूर "Integrated Agriculture development Plan for PVTG Beneficiaries from FRA "या प्रकल्पांतर्गत "वनहक्क कायद्याद्वारे जिमनी प्राप्त असणाऱ्या राज्यातील ५१ आदिम जमातीच्या शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदानावर प्रती शेतकरी ०.२० हेक्टर क्षेत्रावर शेडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे" ही योजना राबविण्यासाठी एकूण रु. ८३२.३२ लक्ष किमतीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक-१ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

- २. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदीच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी करावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
- ३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११५५१९५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रकाश वि. वाजे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १. मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई
- २. मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
- ४. सचिव (कृषि), कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय , मुंबई -३२
- ५. आयुक्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक.
- ६. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे.
- ७. आयुक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- ८. उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ९. सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास.
- जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नाशिक, ठाणे, पालघर, रायगड, यवतमाळ, नांदेड, गडिचरोली, चंद्रपुर.
- ११. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नाशिक, शहापुर, डहाणु,जव्हार,पेण,पांढरकवडा, किनवट,अहेरी,गडचिरोली, भामरागड,चंद्रपुर.
- १२. निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई

परिशिष्ट –१ सन २०१६–१७ मधील आदिम जमाती विकास कार्यक्रम अंतर्गत मंजूर Integrated Agriculture Development Program for IFR beneficiaries योजना

| ٩ | योजनेचे नाव | आदिम जमाती संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत वनहक्क कायद्याद्वारे जिमनी प्राप्त असणाऱ्या ५१ आदिम शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदानावर ०.२० हेक्टर क्षेत्रावर शेडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे. |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २ | योजनेतील लाभार्थी / युनिट संख्या | वनहक्क कायद्याद्वारे जिमनी प्राप्त असणारे आदिम जमातीचे ५१ शेतकरी |
| n | योजनेचे आकारमान | योजनेचे एकुण आकारमान- रु.८,३२,३२,०००.००/- शासन अनुदान रु. ७,९०,७०, ४००.००/- लाभार्थी हिस्सा रु. ४९,६१,६००.००/- एकुण रु. ८,३२,३२,०००.००/- शासन अनुदान, २०१६-१७ करिता आदिम जमाती संरक्षण योजनेंतर्गत Integrated Agriculture development Plan for PVTG Beneficiaries from FRA ह्या कार्यक्रमासाठी मंजुर रु.८००.०० लक्ष निधीमधुन खर्च करणेत येईल. |
| 8 | योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक | लाभार्थ्यांना लाभ देतांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सन २०२०- २१ करीताच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार नमुद दराप्रमाणे खालील मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय असेल रक्कम रुपये लाभार्थी |
| Ч | अंमलबजावणी अधिकारी | एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, नाशिक, शहापुर, डहाणु, जव्हार, घोडेगाव, पेण, पांढरकवडा, किनवट, अहेरी, भामरागड, चंद्रपुर, गडिचरोली. |
| Ę | प्रकल्प राबविणारी यंत्रणा | • संबंधित जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी. |
| 9 | नियंत्रक अधिकारी | • आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. |

| ۷ | योजनेचा हेतू / | फलोत्पादन क्षेत्रात संरक्षित शेती पध्दतीचा अवलंब करून फुले |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | । उद्देश | भाजीपाला पिकाचे अधिक उत्पादन, उत्पादकता व उच्च दर्जा |
| | 04(1 | उत्पादन घेवून शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे. |
| | | वन पट्टेधारक आदिम शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतिच्य |
| | | निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य करणे. |
| | | वनपट्टेधारक आदिंम जमातीतील युवकांना कृषि क्षेत्रा |
| | | स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे. |
| | | फलोत्पादन क्षेत्रात बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च |
| | | तंत्रज्ञाणाचा वापर करण्यासाठी वन पट्टेधारक आदिम जमातीतीत |
| | | शेतक-यांना प्रोत्साहन देणे. |
| | योजना राबविण्याची | योजना अंमलबाजवणीच्या अनुषंगाने आयुक्त आदिवासी विकास |
| 9 | कार्यपध्दती | नाशिक यांच्या स्तरावर खालीलप्रमाणे सनियंत्रण व मूल्यमापः |
| | The state of the s | समिती गठीत करण्यात येईल |
| | | |
| | | १) आयुक्त, आदिवासी विकास -अध्यक्ष |
| | | २) सर्व अपर आयुक्त, आदिवासी विकास - सदस्य |
| | | ३) प्रत्येक अपर आयुक्त कार्यालय कार्यक्षेत्रामधील १ |
| | | याप्रमाणे ४ प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रसदस्र |
| | | ४) जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, नाशिक -सदस्य |
| | | ५) सहायक आयुक्त, केंद्रीय योजना, आयुक्त कार्यालय – सदस् |
| | | सचिव |
| | | • एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत संरक्षित शेती या घटकाव |
| | | राबविण्यात येणा-या योजनेत वन पट्टेधारक आदिम जमातीतीत लाभार्थ्यांना आर्थिक भार भरणे शक्य नसल्याने त्या योजनेस ९ |
| | | • |
| | | टक्के विशेष केंद्रीय सहाय्य अनुदान व ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा य स्वरुपात योजना संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकार |
| | | यांच्यामार्फ़त राबवयाची आहे. |
| | | सदर योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक फलोत्पादन अभियाः |
| | | अंतर्गत संरक्षित शेती घटकावरीलमार्गदर्शक सूचना सन २०२०-२ |
| | | नुसार करण्यात येईल. |
| | | योजना राबविताना काही तांत्रिक/प्रशासकीय अडचणी आल्या |
| | | लक्षांक बदलणे/कमी जास्त करणे/लक्षांक वर्ग करणे या बाबतचे स |
| | | अधिकार सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीस राहतील. |
| | | संबंधित जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, वनहक्क कायद्या अंतर्गः |
| | | जिमनी प्राप्त झालेल्या पात्र आदिम लाभार्थी यांचे कडू |
| | | mahadbtmahait.gov.in पोर्टलवर प्राप्त ऑनलॉईन अर्जांमधु |
| | | लाभार्थ्यांची निवड करतील. |
| | | संबंधित जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, यांचे स्तरावर लाभार्थ |
| | | निवडीचे निकष ठरविणे, एकूण प्राप्त अर्जाची छाननी करणे |
| | | लाभार्थी निवड करणे इत्यादी करीता खालीलप्रमाणे निवड समित |
| | | गठीत करण्यात येईल |
| | | |

| | १) संबंधित जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, -अध्यक्ष २) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, - सदस्य ३) तंत्र अधिकारी, संबंधित उप विभागिय कृषि अधिकारी कार्यालय - सदस्य ४) संबंधित तालुका कृषि अधिकारी, - सदस्य ५) संबंधित तालुका कृषि अधिकारी, - सदस्य पिवत सदर सिनतीमार्फत लाभार्थ्याना निधी वितरणाचे टप्पे निश्चित करण्यात येतील. समितीमार्फत निवड करण्यात आलेल्या पात्र लाभार्थी यांना कृषि विभागा मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. सदर शेड नेट उभारणी सुरु करण्यापूर्वी व काम सुरु असतांना मंडळ कृषि अधिकारी व काम पूर्ण झाल्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी प्रत्यक्ष स्थळ भेट देऊन आवश्यक बार्बीची तपासणी करतील. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी योजना पूर्ण केल्यानंतर योजनेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व फलनिष्पत्ती अहवाल संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांच्या मार्फत आयुक्त आदिवासी विकास, नाशिक यांना सादर करावे. आयुक्त, आ.वि. यांनी सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कार्यपद्धती व नियमानुसार होण्याची दक्षता घ्यावी. प्रकल्पाची छायाचित्रांसह यशोगाथा तयार करणे तसेच योजनेविषयी सर्व माहिती उदा. लाभार्थी यादी, योजना अंमलबजावणीचे फोटो, यशोगाथा, लाभार्थी माहितीचा डेटाबेस इत्यादी अभिलेखात जतन करण्यात यावे. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १० निधी वितरण कार्यपद्धती | Integrated Agriculture development Plan for PVTG Beneficiaries from FRA ह्या कार्यक्रमासाठी मंजुर रु.८००.०० लक्ष पैकी शासन अनुदान रु.७,९०,७०,४००/- चे वितरण खालीलप्रमाणे करणेत येईल. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक हे संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प, यांना लाभार्थ्यांच्या संख्येनिहाय निधी वितरित करतील. प्रकल्प कार्यालयाकडून लाभार्थी संख्या व कृषि विभागाच्या मागणी प्रमाणे २ टप्प्यात निधी कृषि विभागास वितरित करण्यात येईल. पहीला टप्पा-लाभार्थी निवडी नंतर कृषि विभागाच्या मागणीनुसार ८० टक्के निधी वर्ग करण्यात यावा. दुसरा टप्पा- अंतिम मोका तपासणी केल्यानंतर उर्वरित २० टक्के निधी कृषि विभागास वर्ग करण्यात येईल |
| ११ योजनेचा कालाव | ाधी • १ वर्ष |

| 92 | योजनेच्या अटी व शर्थी | लाभार्थी आदिम जमातीचा असावा. अर्जदाराकडे अनुसूचित जमातीचे सक्षम प्राधिका-याचे जातीचे प्रमाणपत्र असावे. अर्जदार वनपट्टा धारक असावा. अर्जदाराकडे सिंचन सुविधा असणे आवश्यक आहे. सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग अथवा इतर कोणत्याही शासकीय विभागाकडून घेतला नसल्याबाबत दाखला लाभार्थी यांनी जोडणे आवश्यक आहे. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी हे लाभार्थ्यांना शेडनेट उभारणी design व त्याबाबत लागणारी आवश्यक तांत्रिक मदत करतील. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी हे योजना अंमलबजावणीचा मासिक भौतिक व आर्थिकप्रगती अहवाल संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना पाठवतील. योजनेची अंमलबजावणी प्रचलित नियम व कार्यपद्धतीनुसार करण्यात यावी. योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून योजना राबवून पुर्ण होई पर्यतचे फोटोग्राफ, सी.डी., लाभार्थ्यांचे मनोगत इ. आवश्यक त्या कागदपत्रांसह योजना राबविल्याबाबतचे संपूर्ण तपशिल प्रकल्प कार्यालयास वेळोवेळी सादर करणे तसेच शेडनेट गृहांचे Geo-Tagging करणे योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेस बंधनकारक राहील. |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | योजनेचे सनियंत्रण व मुल्यमापन | सदर योजनेचे सनियंत्रण व मुल्यमापन हे उपरोक्त नमूद संनियंत्रण व मुल्यमापन समिती मार्फत करण्यात येईल योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर दर ३ महिन्यांनी सदर समितीची बैठक आयोजित करावी. योजनेच्या अंमलबजवाणीत काही बदल, सुधारणा करण्याचे तसेच अडचणी उद्भवल्यास त्याबाबत आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे अधिकार उपरोक्त समितीस असतील. |
| 98 | योजनेची फलनिष्पत्ती | • वनहक्क कायद्यांतर्गत जिमनी प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी लाभार्थीचे संरक्षित शेतीच्या माध्यमातून भाजीपाला पिकांच्या उत्पादनाद्वारे आर्थिक स्थिरीकरण होईल व त्यांचे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण काही अंशी कमी होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल. |